(d) whether the diamond industry in India is suffering due to the monopolistic attitude Hindustan Diamond Company and reluctance on the part of the Government to probe into the irregular activities of the Hindustan Diamond Company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) No, Sir.

(b) The Hindustan Diamond Company Limited does not buy rough diamonds from South Africa.

(c) Nothing adverse has come to the notice of the Government in regard to the operations of the Hindustan Diamond Company Limited which may merit any probe.

(d) The Company is not adopting a monopolistic attitude. It has been rendering a useful service to the small scale diamond manufacturers, Its share in the country's impart of rough diamonds is less than 10%.

काली सूची में दर्ज कंपनियों को नये ठेके दिया जाना

5757. **श्री राम लाल राही** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी० आई० पाइप बनाने वाली 26 कंपनियों को काली सूची में दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कंपनियों के विरुद्ध जिन्हें इस बीच ठेके दिए गए है, जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर 80 करोड़ रुपये की वसूली करने के आरोप थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में निर्देश जारी कर दिए जाने के बाद भी उन्हें ठेके देने के क्या कारण थे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 27 मई 1983 के इकनौमिक टाइम्स में एक बयान प्रकाशित हुआ था, जो कि टिस्को के, श्री रूसी मोदी द्वारा कथित माना जाता है, उसमें यह लिखा था कि दर-ठेके प्राप्त फर्मों ने अपने उत्पादों को, प्राइवेट पार्टियों को, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर-ठेका मूल्यों से कम दरों में बेचा है। इसकी जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निवेदन किया गया है।

अब तक वर्ष, 1983-84 की अवधि के लिए दर ठेके/मूल्य करार केवल पांच फर्मों को दिए गए, इसमें से तीन फर्में नई हैं। तथापि, उनकी क्षमता जी० आई० पाइपों की संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसी रूप में नए टेंडर मांगे गये हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

Nationalisation of Multinational Companies

5759. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise the multinational companies in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) and (c) No, Sir. The operations of foreign